औद्योगिक विकास की जूठन पर निर्भर जनता के लिये बिना जोश का चुनाव

फ़रीदाबाद (म.मो.) औद्योगिक शहर फ़रीदाबाद को मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है-एक वह जहां उद्योगों की मलाई खाने वाले बसते हैं, इसे शहर का पॉश इलाका कहा जाता है, दूसरा वह जहां उद्योगों की जूठन के सहारे ही किसी तरह ज़िंदगी को घसीटा जाता है। यूं तो इन दोनों के बीच में भी काफ़ी जनता बसती है। पर न्तु फ़िलहाल 'मज़दूर मोर्चा' की एक टीम ने इनमें से दूसरे वर्ग के लोग़ों का सर्वेक्षण किया है।

प्रथम वर्ग के लोग जहां पॉश सेक्टरों के आलीशान भवनों में रहते हैं वहीं दूसरे वर्ग के लोग रेलवे लाइन अथवा गंदे नालों के किनारे खाली पड़ी जगहों पर बस गये। दरअसल अनियोजित औद्योगीकरण के चलते कारखानों व उनके मालिकान तथा प्रबन्धकों आदि के लिये तो रिहायशी सेक्टरों की योजना बनाई गयी, लेकिन इनमें काम करने के लिये आने वाले प्रवासी मज़दूरों को बसाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं सोची गयी। ऐसे में जरूरतमंद मज़दूरों ने ख़ुद ही व्यवस्था बनाते हुए गंदे नालों, रेलवे लाइनों, कारखानों के आस-पास बचे-खुचे ज़मीन के टुकड़ों पर रहना शुरू कर दिया। इस तरह से बसे मज़दूरों ने गत 40-50 वर्षों में बड़ी बस्तियों का रूप ले लिया। मज़दूरों ने बड़ी सावधानी से इन बस्तियों के नाम भी शासकों के नाम पर इन्दिरा गांधी कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, संजय कॉलोनी, राहुल कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी आदि-आदि रख छोड़े। प्रशासन द्वारा की जाने वाली संभावित तोड़-फ़ोड़ से बचने के लिये इस तरह के नाम रखे गये थे। यह चाल कई जगह काम भी कर गयी तो कई जगह नाकाम भी रही।

ऐसी ही एक बस्ती है पटेल नगर। शहर के दक्षिण छोर पर बसी यह कॉलोनी प्रताप स्टील व गुड़गांव नहर के बीच पड़ी खाली जमीन पर वर्ष 1970 के आस-पास बसी थी। सन् 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान सब लोग डरके मारे इसे छोड़ कर भाग गये थे। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में लोग़ों ने वापस लौट कर अपने अध-कच्चे-पक्के घरोंदों को फ़िर से आबाद कर लिया था। दस वर्ग गज़ से लेकर तीस वर्ग गज़ तक के इन घरोंदों की बस्ती नहर के साथ-साथ करीब डेढ किलो मीटर लम्बी है जबकि चौड़ाई मात्र 25-30 मीटर से अधिक नहीं। इस बस्ती के एक तरफ़ नहर जो गंदा नाला बन चुकी है, तो दूसरी तरफ़ सेक्टर 4 है। सेक्टर निवासी इन झुग्गीवासियों से बेहद परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि ये लोग बेहिसाब फ़ैलते ही जा रहे हैं। सेक्टर के पार्कों व सड़कों तक अवैध कब्ज़े करते जा रहे हैं। जबकि झुग्गीवासियों का कहना है कि खेलने के लिये पार्क तो उनके बच्चों को भी चाहिये। इस सवाल पर दरअसल दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह उचित हैं। असल समस्या तो सरकार की गलत एवं जनविरोधी आवास नीति से पैदा होती है।

करीब दस हजार की इस बस्ती में सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालय भी खोल रखा है। यद्यपि सर्वेक्षण के समय स्कूल में छुट्टी थी, इसलिये स्थानीय निवासियों ने बताया कि 250 के करीब बच्चे इसमें पढने को आते हैं। पांच अध्यापकों की जगह यहां केवल दो ही नियुक्त हैं। इनमें से भी एक अध्यापिका ठेके पर बताई गयी। सरकारी स्कूल की अव्यवस्था के चलते इस झुग्गी बस्ती में भी छोटे-मोटे तीन प्राइवेट स्कूल चलते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिये 100 रुपया मासिक खर्च कर सकते हैं वे ही अपने बच्चों को इनमें पढाते हैं। जाहिर है सरकारी में तो वही बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल ही बेबस एवं लाचार हों।

स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर किसी सरकारी व्यवस्था के अभाव में 'झोला छाप' डॉक्टरों की दुकानदारी अच्छी चल रही है। ई एस आई सी कवर्ड निवासियों के लिये पास में ही (सेक्टर 7 की) डिस्पेंसरी भी है; लेकिन वहां तो केवल तभी जाना होता है जब मेडिकल सर्टिफ़िकेट की जरूरत हो क्योंकि वहां उपलब्ध इलाज की व्यवस्था भी कोई बहुत सन्तोषजनक नहीं है। न पर्याप्त डॉक्टर हैं न स्टाफ़ और न ही दवाइयां तथा लम्बी लाइनों में लगना पड़ता है वह अलग से। बस्ती में अधिकांश लोग विभिन्न कारखानों में बतौर कैजुअल अथवा ठेकेदारी के तहत नौकरी करते हैं। कुछ लोग दिहाड़ीदार मज़दूर अथवा कारीगर भी हैं। हरियाणा के लोग तो इस बस्ती में नाममात्र को ही हैं, अधिकांश लोग यू पी व बिहार तथा अन्य राज्यों से हैं।

चुनावी माहौल में चुनाव की चर्चा की तो रिक्शा चालक रामबली ने बताया कि यह बस्ती शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रही है परन्तु इस बार मोदी की हवा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बह रही है। जिधर देखो उसी के पोस्टर व उसी का शोर मचा है। ''तुम किसको वोट दोगे?'' ''देखो जी वोट थोड़े ही खराब करना है, जीतने वाले को ही देंगे।'' ''जीतने के बाद मोदी से क्या उम्मीद करते हो?'' ''कोई उम्मीद नहीं, पहले किसी ने क्या दे दिया जो अब कोई कुछ दे देगा। हमारी तो बस ये झुग्गियां बनी रहें, इन्हें न तोड़ा जाय बस इतना ही काफ़ी है।''

बिहार के मधुबनी से आकर यहां सुपर आटो में बतौर कैजुअल नौकरी करने वाले 24 वर्षीय बजरंगी ने बताया कि 12 घंटे की शिफ्ट तथा 4 घंटे की जबरदस्ती ओवर टाइम करने के बाद नींद ही पूरी नहीं हो पाती तो चुनाव के बारे में क्या सोचें। पूछने पर बताया कि वोट तो बना है, पिछले चुनाव में उसने कांग्रेस को वोट दिया था। ''कांग्रेस की ओर से कौन उम्मीदवार था?'' जवाब में सिर हिला दिया मालूम नहीं। वह तो रामबचन ने हम कुछ लोग़ों को अच्छी बढिया पार्टी दी थी, जिसमें अंग्रेजी पीने को मिली थी, बस उसी के कहने पर वोट दे दी। क्या फ़र्क पड़ता है साहब किसी को दे दो एक ही बात है।

अधिकतर लोग़ों के विचार लगभग ऐसे ही थे। 16 वर्षीय ललन से बातचीत करने पर उसने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से एक स्कूटर व बाइक ठीक करने वाले मिस्त्री की दुकान पर काम करता है। पहले करीब 6 माह तो घर से रोटी खानी पड़ती थी। जब कुछ काम सीख गया तो मालिक ने 10-15 रुपया रोज़ाना देने शुरू कर दिये। बढ़ाते-बढ़ाते अब ढाई-तीन हज़ार तक दे देता है। ''पढे कहां तक हो?'' फ़ीस के पैसे तो घर में थे नहीं सरकारी स्कूल में 4-5 साल बैठ आया था। पढाई-वढाई तो कुछ होती नहीं थी, लेकिन हर साल अगली जमात में बैठा देते थे। ऐसे ही समय बर्बाद करने से अच्छा तो कुछ काम सीख कर रोटी कमाने लायक बनना बेहतर समझा। यदि ऐसे ही स्कूलों में बैठा रहता तो आज रोटी का भी कोई साधन न बन पाता।

लोकतंत्र की मर्यादा व शालीनता का उल्लंघन

16 वीं लोकसभा के आम चुनाव का प्रचार अभियान अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुका है और सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पहले के चुनावों के दौरान राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया के ज़रिए इन दलों के प्रवक्ता तथा नेता राष्ट्रीय व जनहित मुद्दों पर अपना कार्यक्रम जनता के सामने रखते थे जिन पर दूसरे दलों द्वारा उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी जाती थी। परंतु इस बार इस स्वस्थ परम्परा को त्याग दिया गया है। जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फिति आदि बोझ तले दबी जा रही है और उसके सामने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। समाज बढते भ्रष्टाचार व अपराधों की समस्या से त्रस्त है। सभी राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचारी, अपराधी व दागी व्यक्तियों की भरमार है, जबकि सभी दल भ्रष्टाचार व अपराधीकरण का मुद्दा बनाए हुए है और देश व समाज के विकास का नारा लगा रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने के ख़िलाफ़ समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी किए हैं। परंतु किसी भी राजनीतिक दल (राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल) द्वारा इन घोषणा पत्रों में वर्णित कार्यक्रम व मुद्दों पर कोई बहस नहीं की गई। परिणामस्वरूप जनता को किसी भी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आश्चर्य है कि मीडिया जो अक्सर सक्रिय होने में कोई देरी नहीं लगाता, इस मामले में रहस्यमय चुप्पी साध रखी है और चुनावी घोषणापत्रों पर कोई बहस भी नहीं कराई गई। जबकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिये चुनावी घोषणा पत्रों पर सार्थक बहस होना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करके केवल रस्म अदायगी की गई है।

एक स्वस्थ जनतंत्र का तकाजा है कि चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए। भाजपा को साफ़ करना चाहिए कि उनका एजेंडा क्या है? जनता को यह जानने का हक है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो उनका उन मामलों पर क्या रूख होगा जिन्हें लेकर वह सरकार की खिंचाई करती रही है। और उसने संसद में गतिरोध बनाए रखा। उदाहरणस्वरूप एफडी आई पर उसका क्या रूख है? महिला आरक्षण, अल्प संख्यक आरक्षण, जातीय आरक्षण, केन्द्र व राज्यों में लोकपाल व लोकायुक्त, अणविक नीति आदि पर उसका क्या स्टैण्ड है? अन्य दलों को भी इन मुद्दों पर अपना रूख स्पष्ट करना है? अगर इन राजनीतिक दलों को विश्वसनीय व प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें जनहित व राष्ट्रहित के मुद्दों पर अपना स्टैण्ड जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने केवल यह घोषणा कि आम चुनाव की कमान राहुल गांधी के हाथ में होगी। कांग्रेस ने राजनीतिक मुकाबले के लिए अपने किसी नेता की बजाए अपनी नीतियों को ही आगे रखा है और उसकी तरफ से इन्हीं को चुनावी मुद्दा बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ़ भाजपा ने नीतियों की अपेक्षा व्यक्तिवाद को अहम बना दिया है। भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मोदी घूम-घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी उन्हीं के नाम पर मोदी सरकार बनाने के लिए वोट मांग रही है। पूरी भाजपा मोदी में समाहित हो गई है।

मोदी यूपीए सरकार की नीतियों की आलोचना तो कर रहे हैं,परंतु जनता को यह नहीं बता रहे कि उनके द्वारा कौन सी वैकल्पिक नीति अपनाई जाएगी। विकास का मुद्दा उछाला जा रहा है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि देश के विकाश के लिए क्या योजना व नीतियां होगी। असली मुद्दों से भटकाने के लिये व्यक्गित हमले किये जा रहे हैं। मोदी अपनी सभी चुनाव सभाओं व रैली में कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी व रॉबर्ट वाड्रा को अपने निशाने पर रखते

शेष पेज 6 पर

तुर्की-ब-तुर्की

''चुनाव अभियान के दौरान आपको सुनना ताज़गी भरा था, जहां आपने साम्प्रदायिक एवं जातीय राजनीति पर लगातार प्रहार किया।'' (भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की तारीफ़ में स्वामी अग्निवेष के खत से)

हमारा कहना है :

- **अगर मोदी ही साम्प्रदाय और जाति के विरोध में खड़ा है तो फ़िर इनके समर्थन में तो कोई खड़ा रह नहीं सकता। मोदी के चेले रामदास कदम ने मोदी की उपस्थिति में मंच से मुस्लिम विरोधी ज़हर उगला था। इसने पहले मुजफ्फ़रनगर दंगों के आरोपी भाजपा विधायकों को मोदी के मंच पर ही सम्मानित किया गया था। इसी तरह, इस चुनाव में पहली बार मोदी सभी को अपनी जाति बताता घूम रहा है। पिछड़ी जाति का कार्ड खेलने को आप जाति-विरोधी होना कहते हैं?**
- **अग्निवेष जी क्या आप एक भी उदाहरण बतायेंगे जहां मोदी ने संघ एवं विहिप की घोर साम्प्रदायिक करतूतों की निंदा की हो। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। स्वयं आपने भी अनेक अवसरों पर इसकी निंदा ही की है। लिहाज़ा अब यकायक ऐसा क्या सबूत आपके सामने आ गया जिसके चलते आपने मोदी को बेगुनाही का प्रमाणपत्र देना तय किया है।**
- **भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्वामी जी आपने अन्ना हज़ारे की पीठ में कांग्रेसी छुरा भोंका था। अब सेकयुलरिज़्म के मुद्दे पर आप भारतीय जनता की पीठ में भाजपाई छुरा घोंप रहे हैं। दोनों अपने निजी स्वार्थ के लिये। जब कांग्रेस ने राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया तो अब मलाई खाने के लिये भाजपा का घर ढूंढ लिया।**
- **वैसे सभी जानते हैं कि स्वामी अग्निवेष राजनीति के मैदान में एक चला हुआ कारतूस है। ऐसे में अगर भाजपा भी चुनाव उपरान्त आपको ठेंगा दिखा दे तो आपका क्या मुंह रह जायेगा?**

भाजपा पूछती है: ''राबर्ट वाड्रा ने ऐसा कौन सा वयापार मॉडल अपनाया जिससे एक लाख की पूंजी लगा कर 3 साल करोड़ बन गये?''

हमारा कहना है:-वही व्यापार मॉडल जो अम्बानी व अडाणी परिवार ने अपनाया। इस मॉडल का नाम है सत्ता से सांठगांठ। अंग्रेजी में इसे कहते हैंक्रोनी केंपिट लिज़्मा फ़र्क केवल इतना है कि अम्बानी व अडाणी प्रत्येक सत्तारूढ दल से सांठ-गांठ करने में सफ़ल रहते है जबकि वाड्रा बेचार कांग्रेस के बलबूते पर ही पनपता है।